काकोरी के शहीदों का ख्वाब अधूरा मिल-जुल उसे हम करेंगे पूरा

सत्यवीर सिंह

"मैं वो आज़ादी चाहता हूँ, जिसमें ग़रीब, सुकून की ज़िन्दगी जिएँ. मैं ख़ुदा से दुआ मांगता हूँ कि जल्दी ही वो दिन आए, जब अब्दुल्ला मिस्त्री, धनिया मोची और किसान, खालिक -उज्ज़मान जगत नारायण मुल्ला (सरकारी वकील) और लखनऊ की छत्तर मंज़िल (अवध के नवाब का महल) में बैठे राजा साहेब महमूदाबाद के सामने, ठाठ से कुर्सियों पर बैठे नज़र आएं." अमर शहीद अशफाकुल्लाह खान आज हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद है. लेकिन, क्या गरीब आज सुकून की वो ज़िन्दगी जी रहे हैं, जिसका ख़्वाब हमारे शहीदों ने देखा था और जिसके लिए वे हंसते हुए फांसी चढ़े थे? क्या आज आज़ाद भारत में, अब्दुल्ला मिस्त्री, धनिया मोची और हमारे किसान सम्मानपूर्ण ज़िन्दगी जी रहे हैं, जैसा हमारी गौरवशाली क्रांतिकारी विरासत के अलंबरदारों ने सोचा था? क्या आर्थिक आज़ादी के बिना आज़ादी की जंग अधूरी नहीं है? अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, अपनी आख़िरी साँस तक अपने-अपने मज़हब मानते रहे, लेकिन मज़हब, उनके क्रांतिकारी लक्ष्य हांसिल करने में लेसमात्र भी रूकावट नहीं बना. आज जब हमारी उस गंगा-जमुनी तहज़ीब को तार-तार किया जा रहा है, तो क्या हम शहीदों के ख़्वाब बिखरते हुए, उस प्यारी बगिया को लुटते-फुंकते हुए चुपचाप देखते रहें? आज के वक़्त में हमारा क्या फ़र्ज़ है? अमर शहीदों के शहादत दिवस पर, उनकी तस्वीरों को फूल मालाएँ चढ़ाना, उनकी याद में चंद नारे लगाना, क्या उन्हें सही माने में याद करने के लिए काफ़ी है?

इन चंद सवालों पर चर्चा करते हुए, अपने विचार रखते हुए, फ़रीदाबाद के मज़दूरों और मज़दूर कार्यकर्ताओं ने काकोरी के अमर शहीदों को उनकी शहादत की पूर्व संध्या, 18 दिसंबर को शिद्दत से याद किया. क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद के आह्वान पर, आज़ाद नगर मज़दूर बस्ती, सेक्टर 24 स्थित 'चन्द्रिका प्रसाद स्मारक सामुदायिक भवन' में दोपहर 2 बजे एक शानदार मज़दूर सभा संपन्न हुई, जिसमें फ़रीदाबाद के आलावा दिल्ली के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र कार्यकर्ताओं, कॉमरेडस हरेन्द्र, पारुल, शालिनी और साथ ही 'इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फेडरेशन (IPSEF)' की दिल्ली ईकाई के सचिव कॉमरेड राकेश भदौरिया ने सक्रिय रूप से भी भाग लिया और अपने बहुमूल्य विचार रख मज़दूरों का हौसला बढ़ाया.

शहीदों को याद करते आजाद नगर निवासी

हॉल को लाल झंडों और अमर शहीदों के विचारों के कोटेसन द्वारा सजाया गया था. सभा का संचालन क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के अध्यक्ष कॉमरेड नरेश ने किया. फ़रीदाबाद से प्रकाशित लोकप्रिय साप्ताहिक मज़दूर मोर्चा के संपादक कॉमरेड सतीश कुमार ने अपने विचार रखते हुए कहा, कि अगर हम अपने अमर शहीदों के प्रति सही में सम्मान प्रकट करना चाहते हैं तो हमें अपने इर्द-गिर्द समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जागरुक होना होगा. दिल्ली में 'न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन' से सम्बद्ध साथी एम एम चन्द्रा ने मज़दूरों को भरोसा दिलाया, कि वे उनके आन्दोलनों में हमेशा उनके साथ रहेंगे. उसी प्रतिष्ठित संस्थान की संपादक महिला साथी आरिफ़ा ने महिलाओं को शिक्षित और जागरुक होने के लिए प्रेरित किया. वे आजकल मज़दूरों के बच्चों को निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने का कोर्स चला रही हैं. उन्होंने बताया कि कम पढ़े होने के बावजूद भी कैसे गरीब परिवारों के बच्चे अपनी मेहनत और लगन से सप्ताह भर में ही कम्प्यूटर पर काम करना सीख जाते हैं.

आज़ाद नगर में, अगस्त महीने में, रेलवे लाइन पर वहशी और हृदयविदारक ज़ुल्म में अपनी मासूम बच्ची खो चुकी, महिला मज़दूर साथी ने भी अपनी वेदना बहुत मार्मिक शब्दों में साझा की. क्रा म मो के सचिव कॉमरेड सत्यवीर सिंह, उपाध्यक्ष कॉमरेड रामफल जांगड़ा, उप-सचिव कॉमरेड विजय सिंह, मज़दूर साथी अरविंद, सुभाष, खुशाली अहिरवार, लखानी फैक्ट्री के संघर्षरत मज़दूर साथी रजनीश, भूपेन्द्र और भरत ने भी अपने विचार रखे. कॉमरेड विजय द्वारा गाए क्रांतिकारी गीत, ज़ोरदार नारों और काकोरी के अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाने की ज़द्दोज़हद में समर्पित होने के अहद के साथ शाम 6 बजे सभा संपन्न हुई.

उपायुक्त के आदेश की उल्लंघना कर विधायक सीमा ने अवैध गेट लगवाया

फ़रीदाबाद (म.मो.) एनएच तीन निवासी समाज सेवी विष्णु गोयल ने शहर भर की गलियों में गेट लगा कर रास्ते रोकने के विरुद्ध उपायुक्त, निगमायुक्त, प्रशासक हूडा, तथा पुलिस आयुक्त को मार्च 2022 में पत्र लिखा था। पत्र में इन अवैध गेटों से होने वाली असुविधाओं का विवरण भी दिया गया था।

पत्र के जवाब में तत्कालीन उपायुक्त ने निगमायुक्त तथा हूडा के प्रशासक को इस बाबत पत्र लिख कर अनुरोध किया था कि इस तरह के गेटों को न लगने दिया जाय। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से उपायुक्त के साथ-साथ शिकायतकर्ता विष्णु गोयल को भी अवगत कराया जाय। साल खत्म होने को आया है किसी अफसर ने इस मामले में कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं समझी।

हां, उपायुक्त के उक्त आदेश की जानकारी से अवगत लोग जरूर अवैध गेट लगाने से घबराने लगे थे। इस घबराहट को दूर करने के लिये एनएच तीन के लोगों ने अपनी विधायक सीमा त्रिखा का सहारा लिया। नेताओं की यह विशेषता है कि जायज व उचित काम ये लोग भले ही न करा पायें लेकिन गलत एवं गैर कानूनी काम कराने में कभी कोताही नहीं करते। प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा कर, लोगों के बीच ये अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का कोई मौका नहीं चूकते।

बीते सप्ताह एनएच तीन के ई-ब्लॉक में एक अवैध गेट का उद्घाटन करती विधायक सीमा त्रिखा

तालेजड़ित इन गेटों पर बड़े-बड़े विज्ञापन आदि लगा कर गली के ठोंडे तथाकथित आरडब्लूए बनाकर मोटी वसूली करते हैं। इन अवैध विज्ञापनों को उखाड़ने के लिये बने निगम दस्ते को भी इस अवैध कमाई में से उपयुक्त हिस्सा नियमित रूप से दिया जाता है जो उपर तक पहुंचता है।

पर्यावरण के नाम पर अब ढाबों की भी लूट शुरू

करनाल (म.मो.) प्रदूषण को लेकर अब तक पराली जलाने के नाम पर किसानों के पीछे पड़ी थी सरकार। प्रदूषण का सारा दोष पराली के धुंए से बताया जा रहा था। बीते दो माह से, पराली समाप्त हो जाने के बाद भी प्रदूषण में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। अब पर्यावरण विभाग की गिद्ध-दृष्टि ढाबे वालों पर पड़ी है। समझ नहीं आता कि ढाबों अथवा भोजनालयों द्वारा प्रदूषण कैसे फैल सकता है? आजकल शायद ही कोई ढाबा खाना पकाने के लिये गैस का प्रयोग न करता हो। हां, तंदूर गर्म करते समय जरूर कुछ लकड़ी आदि को जलाया जाता है।

यदि खाना पकाने व खाने-खिलाने से ही प्रदूषण फैलता है तो प्रत्येक घर इसके लिये दोषी है। कुछ गरीब घर तो ऐसे हैं, खास तौर पर झुग्गी-बस्तियों में जो महंगी गैस का प्रयोग नहीं कर सकते, वे लकड़ी उपले आदि जला कर ही खाना पकाते हैं। ऐसे में ये तमाम घर प्रदूषण फैलाने के लिये दोषी करार दिये जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि मोदी सरकार एक दिन सभी घरों को इसके लिये दोषी मानने लगेगी। एक और मजे की बात यह है कि पर्यावरण विभाग की मार छोटे-मोटे ढबों एवं भोजनालयों पर ही पड़ रही है। जगह-जगह पर खुले हरियाणा टूरिज्म के ढाबों की तरफ़ झांकने तक कि हिम्मत यह महकमा नहीं जुटा पा रहा। इसके अलावा बड़े-बड़े होटलों में तो ये लोग घुसने की सोच तक भी नहीं सकते।

असल मक्सद इन ढाबों से ठीक उसी तरह मंथली वसूलना है जिस तरह छोटे अस्पतालों व क्लीनिकों से मंथली वसूली जा रही है। इस विभाग को टूटी सड़कों से

उड़ती धूल वाहनों द्वारा उगला जा रहा धुंआ तथा कारखानों से निकलता काला धुंआ भी नज़र नहीं आता। फैक्ट्रियों से निकलता रसायनयुक्त जहरीला पानी भी इन्हें नहीं अखरता। शहरों की गली-गली में उफनते सीवर तथा उनसे फैलती बदबू से भी इस विभाग को कोई ऐतराज नहीं। इन्हें तो बस, पराली के बाद अब ढाबे नजर आने लगे हैं। विभागीय अधिकारी एक बेमानी सा तर्क जरूर दे सकते हैं कि ढाबों से निकलता बचा-खुचा खाना प्रदूषण फैलाता है। यह तर्क पूर्णतया निराधार है। हर ढाबे से बचा-खुचा भोजन एवं जूठन को सूअर पालने वाले बाकायदा खरीद कर ले जाते हैं। ऐसे में फ़िर प्रदूषण फैलाने को बचा ही क्या है?

इन्हीं बेबुनिया तर्कों के आधार पर यहां दो ढाबों को सील बंद करके उनकी बिजली भी काट दी गई है तथा अगले सप्ताह तक दो और ढाबों की भी यही हालत होने वाली है।